

आर्थिक सुधारों के प्रणेता डा. मनमोहन सिंह नहीं रहे

भारत और चीन एलएससी पर जमीनी स्थिति बहाल करने पर हुए सहमत

नयी दिल्ली 26 दिसंबर । पूर्ण प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार देर शाम राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे। डॉक्टर सिंह को सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स ने एक विज्ञप्ति में बताया कि डॉक्टर सिंह को आठ बजकर पांच मिनट पर अस्पताल लाया गया और उन्हें तुरंत चिकित्सा प्रदान की गई। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद डॉ सिंह का नौ बजकर 51 मिनट पर निधन हो गया।

डॉक्टर सिंह के निधन का समाचार मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कल्याण क्षेत्री जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा अस्पताल पहुंची।

डॉ मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पाकिस्तान में हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया। मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी. फिल. की डिग्री ली। डॉ सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और तीन बेटियां उषादेव सिंह, दमन सिंह और

पुरस्कार और सम्मान:

डॉ मनमोहन सिंह को मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में सबसे प्रमुख है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मविभूषण, जो उन्हें वर्ष 1987 में मिला। इसके अलावा, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1995), वर्ष के वित्तमंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड (1993 और 1994), वर्ष के वित्तमंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड (1993), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार (1956), कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार (1955)। मनमोहन सिंह को जापानी निहोन किजई शिम्बुन एवं अन्य कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपाधियों प्रदान की गई हैं।

अमृत सिंह हैं। मनमोहन सिंह की प्रस्तुत इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोसेक्ट्स फॉर सेलफ सस्टेड ग्रोथ भारत की अन्तर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉ सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर भी काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1978 तथा 1990 में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉ सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किये गये। इसके तुरन्त बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के

नई दिल्ली, 26 दिसंबर । रक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों के लिहाज से वर्ष 2024 खास रहा है। भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने नए जोश के साथ आगे कदम बढ़ाया। चार साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन ने कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर बातचीत की। इसके बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएससी) के कुछ क्षेत्रों में जमीनी स्थिति बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वर्षांत समीक्षा में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपये (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष 15,920 करोड़ रुपये था। यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में भारत का रक्षा निर्यात 32.5 फीसदी से अधिक बढ़ा है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में निर्यात में 31 गुना वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू सहित रक्षा उद्योग ने अब तक के सबसे अधिक

निर्यात को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हैं। निजी क्षेत्र और डीपीएसयू ने क्रमशः लगभग 60 फीसदी और 40 फीसदी का योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया है कि 2029 तक 50 हजार करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और डीपीएसयू के आयात को कम करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग ने जुलाई में 346 वस्तुओं वाली पांचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (पीआईएल) अधिसूचित की। इनमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिसेसमेंट यूनिट, सिस्टम, सब-सिस्टम, असेंबली, सब-असेंबली, स्पेयर और कंपोनेंट और कच्चा माल शामिल है। इससे पहले डीपीएसयू के लिए 4,666 वस्तुओं वाली चार पीआईएल अधिसूचित की गई थी, जिनमें से 2,972 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 3,400 करोड़ रुपये है। डीपीएसयू के लिए ये पांच सूचियां सैन्य मामलों के विभाग की ओर से

अधिसूचित 509 वस्तुओं की पांच पीआईएल के अतिरिक्त हैं। इन सूचियों में अत्यधिक जटिल सिस्टम, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं। रिकॉर्ड-उच्च आंकड़े पर पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के रक्षा उत्पादन की तुलना में 16.7 फीसदी की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन का मूल्य 1,08,684 करोड़ रुपये था। 2023-24 में उत्पादन के कुल मूल्य में से लगभग 79.2 फीसदी का

योगदान डीपीएसयू से और 20.8 फीसदी का योगदान निजी क्षेत्र ने किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2029 तक तीन लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

सी-295 टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्सप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेंशिश राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज ने अक्टूबर, 2024 में गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवॉरंस सिस्टम्स लिमिटेड कैम्पस में सी-295 परिवहन विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।सितंबर, 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 56 विमानों की आपूर्ति के लिए स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे।

पुलिस ने अवैध शराब की 12 बोतलों के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार

पुंछ, 26 दिसंबर । जिले से अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के निरंतर प्रयास में पुंछ पुलिस ने एक तस्कर को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से अवैध शराब जब्त की है।

क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन के बारे में एक विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन पुंछ के एसएचओ के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने त्वरित कार्रवाई की और उक्त तस्कर को रोका और उसके कब्जे से 12 बेतलें शराब बरामद की।

आरोपी व्यक्ति की पहचान शैद खान पुत्र जाफर खान निवासी लसाना तहसील सुरनकोट और जिला पुंछ के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन पुंछ में धारा 48 (ए) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

गोवंश तस्करी की कोशिश नाकाम की, 15 गोवंश को बचाया, वाहन जब्त

सांबा, 26 दिसंबर । गोवंश तस्करों और उनके समर्थकों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए सांबा पुलिस ने लगातार दूसरे दिन पुलिस स्टेशन घगवाल के अधिकार क्षेत्र में गोवंश तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। गोवंश तस्करों के चंगुल से पंद्रह गोवंश को बचाया और गोवंश के अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया।

एसएचओ पीएस घगवाल के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन घगवाल की एक पुलिस टीम ने एनएचडब्ल्यू नाका तपयाल पर वाहन चेकिंग ड्यूटी करते समय कटुआ की तरफ से आ रहे एक ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर जेके02एबी-9535 को चेकिंग के लिए रोकने का इशारा किया। लेकिन चालक ने वाहन रोकने के बजाय गति बढ़ा दी और मौके से भागने की कोशिश की।

सतर्क पुलिस दल ने वाहन का सफलतापूर्वक पीछा किया और नाका प्वाइंट से कुछ दूरी पर उसे रोक लिया। वाहन की जांच के दौरान वाहन के अंदर पंद्रह गोवंश लदे हुए पाए गए जिन्हें क्रूर तरीके से बांधा गया था और बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। सभी बचाए गए गोवंश को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। थाना घगवाल में एफआईआर संख्या 181/2024 यू/एस 223 बीएनएस, 11 पीसीए एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों की शिकायतें सुनीं

पर प्रकाश डाला और उनकी आजीविका की सुरक्षा में सरकार से सहयोग मांगा। इसी तरह, हॉट मिक्स प्लांट मालिकों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपने उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया और समय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। अपने राज्य अध्यक्ष के नेतृत्व में जेएचडी केजुअल लेबरर्स यूनियन प्रॉन्ट ने केजुअल मजदूरों के कल्याण के बारे में चिंता जताई, जबकि फ़िजियोथेरेपिस्टों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों के बारे में जानकारी दी, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों ने अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को प्रस्तुत किया और कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति ने कर्मचारियों के कल्याण को व्यापक रूप से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रीनगर 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने यहां राबता कार्यालय में अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान यह बात कही, जहां कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए कई प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने अपनी चिंताओं और मांगों को प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा, कारीगर, श्रम और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की, जिन्होंने तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले मुद्दों को सामने रखा।

प्रतिनिधियों में से, जम्मू-कश्मीर कॉलेज शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से जम्मू-कश्मीर में कॉलेज शिक्षकों की सेवाविधुति आयु बढ़ाने की मांग पर विचार करने का आग्रह किया।

विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों द्वारा बने कश्मीरी शॉल निर्माता कल्याण फ़ेडरेशन ने पारंपरिक शॉल बनाने के व्यापार के सामने आने वाली चुनौतियों

गुरुग्राम में मृत मिली जम्मू निवासी आरजे सिमरन सिंह

गुरुग्राम, 26 दिसंबर । जम्मू की धड़कन नाम से मशहूर आरजे (रेंडियो जॉकी) व इस्टग्राम इन्फ्लुएंसर सिमरन सिंह गुरुवार को गुरुग्राम स्थित आवास पर मृत मिली। सिमरन यहां किराए के घर में रह रही थीं। उसका शव फंसे से लटका हुआ मिला। सिमरन सिंह रेंडियो मीर्वी में भी आरजे रह चुकी थीं। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके फैंस में भी शोक की लहर दौड़ गई।

सिमरन सिंह के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर हैं।

पुलिस के अनुसार आरजे सिमरन सिंह जम्मू के गांव नानक नगर की रहने वाली थीं। वह सेक्टर-47 गुरुग्राम स्थित स्थित मकान नंबर-58 में अपने कुछ दोस्तों के साथ किराये पर रहती थीं। वह अपने कमरे में फंसे पर लटकी मिली।

जम्मू-कश्मीर में 100 प्रतिशत मीटरिंग के बाद 24x7 बिजली मिलेगी : उमर

श्रीनगर, 26 दिसंबर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में 100 प्रतिशत मीटरिंग हो जाने के बाद निबांधे बिजली मिलेगी अनिर्धारित बिजली कटौती के मुद्दे को संबंधित करते हुए उमर ने अत्यधिक और अनधिकृत बिजली उपयोग के कारण सिस्टम पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण दबाव को स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से बिजली की खपत को सुव्यवस्थित करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चार बत्तों के लिए बिजली का उपयोग करने के लिए समझौता किया है लेकिन वे चार हीटरों के बराबर बिजली की खपत करते हैं। इससे सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ता है। कठोर सख्ती के क्षेत्र की परेशानियों को और बढ़ा दिया है पानी की पाइपें जमने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उन्होंने बर्फबारी की उम्मीद जताई जिससे मौसम की स्थिति में सुधार होगा और कुछ चुनौतियाँ कम होंगी। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शासन की मौजूदा चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ मुद्दे तब अब तक नहीं होंगे

उत्तर भारत में हो सकती है बारिश, कोहरे के कारण 34 ट्रेनें देर से चलीं

नई दिल्ली, 26 दिसंबर। उत्तर भारत में भीषण शीत लहर जारी है, वहीं दिल्ली में भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन यानि 27 और 28 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का अनुमान जताया है। वहीं, कोहरे की स्थिति को देखते हुए गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कम दृश्यता प्रक्रियाओं के बारे में यात्रियों को सूचित करने के लिए सलाह जारी की है। कोहरे के कारण गुरुवार को 34 ट्रेनें देरी से चलीं।

ट्रेनों पर कोहरे की मार घने कोहरे के कारण गुरुवार को दिल्ली से देश के विभिन्न भागों में जाने वाली 34 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं।

प्रभावित ट्रेनों में आनंद विहार जनसाधारण एक्सप्रेस और पद्मावत

हमारा मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के दिल में प्रेम, दया और भाईचारे का दीप जलाना है : एलजी

जम्मू 26 दिसंबर।उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 'ऑल जेएंडके क्रिश्चियन सभा' द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लिया।

उन्होंने बिशाप, पुजारियों और सीएनआई चर्च, जम्मू-श्रीनगर डायोसिस और ऑल जेएंडके क्रिश्चियन सभा के सदस्यों के साथ बातचीत की और एक शांतिपूर्ण, निस्वार्थ, दयालु और देखभाल करने वाले समाज के निर्माण में उनके योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा, ईसाई समुदाय ने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दूसरों को प्रेरित करेगी।

रोपवे परियोजना के विरोध में कटड़ा कस्बा दूसरे दिन भी बंद रहा

जम्मू, 26 दिसंबर । रोपवे परियोजना के विरोध में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के 72 घंटे बंद के आह्वान के दूसरे दिन गुरुवार को

मुख्य सचिव द्वारा आरएमपी के तहत एमएसएमई को समर्थन देने हेतु सर्वोत्तम कार्यान्वयन रणनीति अपनाने पर जोर

जम्मू 26 दिसंबर।मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक बैठक आयोजित की, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और गति देने की योजना के जम्मू एवं कश्मीर में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई योजना का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया गया।

बैठक में आयुक्त सचिव आई एंड सी विभाग, जेकेटीपीओ के एमडी, उद्योग निदेशक कश्मीर/जम्मू, आईआईएम जम्मू, नाबार्ड, सिडबी के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए स्वीकृत रणनीतिक निवेश योजना

जलाना है।उपराज्यपाल ने कहा, क्रप्रभु ईसा मसीह ने व्यक्ति के विचारों की शुद्धता, नैतिक कार्य और बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छे कर्म करने पर जोर दिया। प्रभु ईसा मसीह के आदर्शों का पालन करने और निस्वार्थ सेवा को अपना आदर्श बनाने की जरूरत है।

मुख्य सचिव द्वारा आरएमपी के तहत एमएसएमई को समर्थन देने हेतु सर्वोत्तम कार्यान्वयन रणनीति अपनाने पर जोर

जम्मू 26 दिसंबर।मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक बैठक आयोजित की, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और गति देने की योजना के जम्मू एवं कश्मीर में कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई योजना का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया गया।

बैठक में आयुक्त सचिव आई एंड सी विभाग, जेकेटीपीओ के एमडी, उद्योग निदेशक कश्मीर/जम्मू, आईआईएम जम्मू, नाबार्ड, सिडबी के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जम्मू एवं कश्मीर के लिए स्वीकृत रणनीतिक निवेश योजना

अटल डुल्लू ने इस अवसर पर संबंधितों को इस योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि इस योजना में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने की काफी क्षमता है। इसका बेहतर

बच्चों के लिए 'फील गुड फैक्टर' दादा-दादी

बुजुर्ग जीवन को विस्तार देते हैं, गहराई देते हैं। वे आपके पास्ट का अटूट हिस्सा हैं। उन्हीं के कारण आपका वजूद है।

आज की पढ़ी-लिखी हाई सोसायटी से यह आम शिकायत है कि मां-बाप अपने बच्चों को दादा-दादी के पास फटकने तक नहीं देना चाहते क्योंकि वे अपने बच्चों को लेकर ओवर पोजैसिव रहते हैं। जो साथ रहते हैं वे बच्चों के साथ मिल कर उनके खिलाफ पार्टीबाजी कर लेते हैं। दादा-दादी में से अगर एक भगवान को प्यारा हो गया तो बहू को और मनमानी की छूट मिल जाती है। कमजोर पार्टी को दबाना उसके लिए और भी आसान हो जाता है।

दादा-दादी के साथ पोते-पोती का जो एक खास जुड़ाव लगाव होता है वह आज की विषैली फिज़ा में बुरी

तरह प्रभावित हो रहा है। टी.वी. सीरियल्स मन पर बहुत ही गलत असर डाल रहे हैं। इसका उदाहरण है प्रसिद्ध मैगा सीरियल, सास भी कभी बहू थी में पोती भूमि का अपनी दादी को 'ए तुलसी' कह कर संबोधित करना। भारतीय संस्कृति आज कहां पर पहुंच गई है।

बदलाव जरूरी है स्वाभाविक है यह सब तो ठीक है लेकिन बदलाव के नाम पर पतन के गर्त में जाना उचित नहीं है। जन्म देने वालों और पाल पोसकर बड़ा करने वालों को अपमानित कर क्या सिद्ध करना चाहती है आज की यह सभ्य सो कॉलड पढ़ी-लिखी पीढ़ी।

दादा-दादी बच्चों के जीवन में फील गुड फैक्टर होते



हैं, सुरक्षा कवच, कम्फर्ट जोर और भविष्य में उनकी उम्र पर पहुंचने पर मधुर यादों का जखीरा।

आज के मां-बाप जब अपनी दुष्टता के चलते उनके बीच में कोई संबंध जुड़ने ही न देंगे, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होने देंगे तो बच्चों के दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन रह जाएगा क्योंकि मां-बाप अपनी जगह हैं दादा-दादी अपनी जगह।

दादा-दादी उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए होते हैं जहां जाकर एक ठहराव ज्यादा मैच्योरिटी और समझ आ जाती है। इसके अलावा अब वे सेंकेंड चाइल्डहुड जी रहे होते हैं। ऐसे समय में वे अपने पोते-पोती के बेहतर दोस्त साबित हो सकते हैं।

बच्चे उनसे जीवन में कितनी अच्छी बातें और संस्कार सीखते हैं जो उनके व्यक्तित्व में गहराई तक उतर कर उन्हें भविष्य में बेहतर इंसान बनाते हैं यह सिर्फ समझने की बात है। बच्चे अपने मां-बाप को उनके मां-बाप की इज्जत करते, केयर देखते हैं तो स्वतः ही ये बातें उनके संस्कारों में आ जाती हैं। भले ही आप अपने मां-बाप से दूर रहते हों, बच्चों को उनसे जोड़ कर रखें, उन्हें रैगुलर टच में रखें, फोन, विजिट या पत्र ई-मेल के द्वारा ही नहीं। वक्त की नज़ाकत पहचान कर दादा-दादी भी अपने को समयानुसार ढाल लें तो अच्छा है। उन्हें दखलअंदाजी से दूर रहना चाहिए और बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए जब तक कि बात सीरियस अंजाम की ही न हो। अब वक्त उनका है। उन्हें अपने ढंग से जीने दें और बच्चों को भी अपने ढंग से पालने दें। उनकी खुशी में खुश होना सीख लें।

बुजुर्ग जीवन को विस्तार देते हैं, गहराई देते हैं। वे

आपके पास्ट का अटूट हिस्सा हैं। उन्हीं के कारण आपका वजूद है। आप जो सांसें ले रहे हैं ये उनकी ही देन हैं। उनके साथ जीवन मूच्य हैं। आज के आपाधापी और तनावग्रस्त माहौल में उनके पास शीतल छाया है। संतुलन है और आपके लिए रिड्रेशनोंरेंस इसीलिए शायद आज दुनिया में कई जगह २दादा-दादी गोद लिए जाने लगे हैं।

अपने बच्चों को जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, दादा-दादी के प्यार से वंचित न रखें। उनको लेकर अपने पोजैसिवनेस के लिए स्वयं दादा-दादी बनने पर कहीं अपने प्रति इसी तरह के व्यवहार को पाकर बाद में आपको पछताना न पड़े।

ऐसे लगाएँ मस्कारा

पहली बार किसी मस्कारे का प्रयोग करने से पहले उसे दो-तीन घंटे पहले हथेली के पीछे की त्वचा पर लगाकर ट्रायल लें ताकि यह पता चले कि मस्कारा आपको सूट कर रहा है या नहीं। अगर मस्कारा लगाने से आपके आँखों में खुजली हो रही है, आँखें लाल हो रही हैं या फिर पलकें झड़ रही हैं तो उस मस्कारे का प्रयोग एकदम बंद कर दें। आमतौर पर युवतियों महिलाओं से मस्कारा एक बार में नहीं लगता। इसलिए कांस्टेंट होकर मस्कारा लगाएँ। मस्कारे को पीछे से आगे की ओर बढ़ाकर प्रयोग करें। ताकि वह सही ढंग से पूरी बरीनियों पर फैल सके। मस्कारे के फैलने पर उसे छुड़ाने के लिए क्लीजिंग मिल्क या गुलाबजल की रूई के फाड़े पर लगाकर मस्कारा छुड़ाए या आई मेकअप रिमूवर का प्रयोग करें। सखा कपड़ा या टॉवेल का प्रयोग कलसे से पलकों को नुकसान पहुँचता है। अगर आपकी पलकें झड़ रही हैं या फिर आँखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा है तो आँखों को ठीक होने तक मस्कारे का प्रयोग न करें।

बुरा काम है दांपत्य में सैंधमारी

दांपत्य जीवन को हमेशा रथ के दो पहियों से निरूपित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों पहियों का सही चलना दांपत्य जीवन की गाड़ी के लिये जरूरी है। बिना आपसी समझ और आपसी प्यार के यह संभव नहीं होता, इसलिये आपसी विश्वास को बनाये रखें। एक-दूसरे पर विश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है।



दिखावे के बाद अब बड़े-ठाठ से अपने प्रेमी संजीव की दूसरी पत्नी बनकर रहने लगी। प्रेम का एक धिनौना रूप यह भी है।

दूसरों का घर उजाड़ने वाली ऐसी सेंधमार महिलाओं का कहना है कि प्यार के लिए सामाजिक स्वीकृति वे ही चाहते हैं, जो भीरू होते हैं।

आजाद देश में हर महिला को इस बात की पूर्ण आजादी होनी चाहिए कि वह जिससे चाहे प्यार करे, जिसके साथ चाहे अपनी दुनिया बसाए।

विनय और मोना का प्यार परवान चढ़ता, इससे पहले ही विनय की शादी डॉक्टर अंजलि से हो गई। अंजलि चूँकि डॉक्टर थी, वह अस्पताल और मरीजों में व्यस्त रहती। किचिन में तरह-तरह की चीजें बनाकर पति को खिलाने के लिए भला उसे फुर्सत कहां थी। अंजलि की व्यस्तता का फायदा मोना ने खूब उठाया। उसके अस्पताल जाने पर वह अपने प्यार को 'प्लेटैनिक' दोस्ती का नाम देकर, तब तक अपने मित्र रिश्तेदारों को छलती रही, जब तक कि बिब्ली के भाग से छींका न टूटा। अंजलि के गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। कोई इलाज न बचा और आखिर वह असमय ही चल बसी। अंजलि की मौत को अभी चंद महीने भी न हुए थे कि मोना उसकी जगह विनय की दूसरी पत्नी बनकर आ गई।

प्यार करना जुर्म नहीं, लेकिन किसी शादीशुदा पति या पत्नी से प्यार जताना बेशक जुर्म की श्रेणी में ही आता है। यह बात अलग है कि कानून इसके लिए किसी को सजा नहीं दिला सकता। एक समर्पित भारतीय पत्नी के लिए पति उसके अपने जीवन से बढ़कर होता है। उसकी मृत्यु के बाद वह जीवित लाश बनकर रह जाती है। ऐसी समर्पित पत्नी से उसका पति छीनकर दूसरी स्त्री ठीक करती है या गलत, यह उसकी अपनी सोच है, लेकिन एक पत्नी से उसका जीवन छीन लेना, कल्ल करने से छोटा अपराध कहाँ नहीं है। इसी तरह किसी पागल प्रेमी की हद तक पत्नी को चाहने वाले पति से उसकी पत्नी छीन लेना भी उतना ही संगीन अपराध है।

कामयाबी का आकाश छूने को तैयार

बेटियां



पुरुष प्रधान समाज के कूर पंजों की पकड़ से नारी अब आजाद होने लगी है। सदियों से उत्पीड़न और शोषण की शिकार बेटियां, अपनी मेहनत सुझ-बुझ और उत्साह के बूते जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के नये-नये अध्याय लिख रही हैं। वे परिवार, समाज तथा देश को आगे ले जाने को तैयार हैं। समय भी सत्य और संकल्पों का सुधी होता है, इसलिए पक्के इरादों वाली बेटियों के रास्ते में आज कोई अवरोध अधिक देर नहीं टिकता। सत्य की राह पर चलते हुए लक्ष्य पर निगाहें, उन्हें हर मंजिल तक पहुंचाने में मदद्गार साबित होती हैं।

जीतने का जज्बा, हाल को कोसों दूर भगा देता है। उसी जीत के जज्बे ने आज बेटियों के सामने मेधा पाटकर, किरण बेदी, सानिया मिर्जा, इंदिरा न्यूयी, कल्पना चावला, सुनीता विलीयम जैसी शख्सियतों को सामने ला खड़ा किया है, जिनके आगे हर मुश्किल नतमस्तक हो जाती है। मेधा पाटकर ने नर्मदा विस्थापितों की हक की लड़ाई के लिए खुद को आगे कर दिया, वहीं किरण बेदी 'असंभव कुछ भी नहीं' की लाइन पर चलते हुए, बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बन गयीं। आज लगभग हर क्षेत्र में सफलता के नित नए मुकाम हासिल करती बेटियां, आज हर पल जीतने के लिए तैयार हैं।

प्यार भी बड़ी अजीब शौक है। यह तो बस हो जाता है। कब, क्यों और कहां, यह कुछ निश्चित नहीं है। प्यार करने वालों को प्यार का ऑब्जेक्ट दुनिया में सर्वाधिक हसीन लगता है, चाहे वह बदसूरत ही क्यों न हो। ऐसा न होता तो हमारे पड़ोसी 'किसलय रहेजा' जैसे बदशकल और रुखे इंसान के पीछे संजना यूं ही बाबरी न होती। उनकी पत्नी के सीधेपन का भी फायदा संजना को मिल गया। चंचल और स्मार्ट संजना रिश्ते में हालांकि 'किसलय' की कुछ दूर की बहन लगती थी। 'किसलय' की शादी उसके मां-बाप से कभी न करते, यह बात वे स्वयं भलि-भांति जानती थी। इन समीकरणों में संजना ने कृष्ण की राधा की भांति ही 'किसलय' के जीवन में जगह ले ली थी।

एक थे संजीव पांडे, जर्मींदार और उस पर भी बड़े राजनेता। दिखने में भी काफी सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक। माता-पिता ने उनकी शादी जर्मींदार घराने की एक कम पढ़ी-लिखी सुंदर, सुशील कन्या से कर दी थी।

एक-एक करके वह चार बच्चों की मां बन गई। संजीव को एक तो पहले से ही वह पसंद नहीं थी, जिस पर चार बच्चों की मां हो जाने पर वह उससे और भी खिंचा रहने लगा था। नमिता उसके दोस्त की पत्नी थी। नमिता के हावभाव में उसे आमंत्रण दिखाई दिया। अपने प्रेम को शक से बचाए रखने और संजीव तथा उसकी पत्नी ऐश्वर्या के दांपत्य में सेंधमारी करने के लिए नमिता ने विवाहित प्रेमी के बच्चों को फुसलाने का षड्यंत्र रचा। वह उनके लिए तोहफे खरीदती, कभी उन्हें होटलों में ले जाती, कभी पिक्नर दिखाती। किशोरावस्था में बच्चों में सही-गलत की इतनी पहचान नहीं हो पाती है। बच्चे भी नमिता आंटी के सामने अपनी मां को फूहड़ समझने लगे। अब नमिता का दूसरा कदम था प्रेमी के साथ मिलकर, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसका कल्ल करवाना। कानून उसका कुछ न बिगाड़ सका। नमिता कुछ दिनों के शो के नाटक और श्वेत वस्त्रों के

संपादकीय

समानांतर सत्ता केंद्र व्यावहारिक नहीं

जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के निर्देशों का विरोध करने के लिए यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम प्रतीत होता है, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो जम्मू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ने हाल ही में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय को तीन साल का सेवा विस्तार दिया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पुनर्नियुक्ति, सेवा विस्तार, अतिरिक्त प्रभार और संलग्नक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सीएम उमर द्वारा दिया गया यह आदेश विशेष रूप से यूटी के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए था, लेकिन इस कदम के पीछे का विचार कमोबेश पारदर्शिता लाने और पक्षपात से निपटने के लिए था।

यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि एलजी सिन्हा के कार्यालय ने एसकेयूएएसटी-कश्मीर के कुलपति प्रोफेसर नजीर गनई का कार्यकाल भी दो साल के लिए बढ़ा दिया है। एलजी कार्यालय द्वारा लिए गए ऐसे विपरीत निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल (एलजी) प्रशासन के बीच चल रहे ‘संघर्ष’ को उजागर करते हैं। निश्चित रूप से, उमर अब्दुल्ला की स्थिति के विपरीत एलजी द्वारा उठाए गए इस कदम ने दो शासकीय प्राधिकरणों के बीच तनाव को जन्म दिया है, जिनमें से एक का नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधि कर रहे हैं, और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा।

जम्मू-कश्मीर में इन समानांतर सरकारों के बीच चल रहा अघोषित संघर्ष शासन और संस्थागत कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा करता है। विस्तार जैसे मामलों पर परस्पर विरोधी निर्णय एकजुट शासन की कमी का संकेत देते हैं, जो अंततः सार्वजनिक सेवाओं और नीतियों के प्रभावी वितरण को प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले में जो बात मायने रखती है, वह है क्षेत्र की आबादी पर पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि यह इस झगड़े के बीच में फंस गया है, जहाँ एलजी सिन्हा और सीएम उमर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग परेशान हैं। फिर भी, समय आ गया है कि सत्ता में बैठे लोगों को शासन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर मिलकर काम करना चाहिए, जो हाल ही में क्षेत्र के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।

उपरोक्त कुलपतियों को सेवा विस्तार देने का मुद्दा निस्संदेह जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल का विशेषाधिकार था, क्योंकि वे शिक्षा के उक्त उच्चतर संस्थानों के प्रमुख हैं, लेकिन क्षेत्र में जो संदेश फैला है, वह बहुत आशाजनक और व्यावहारिक नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोगों के विरोधी रुख लोगों को बहुत गलत संकेत देते हैं, जो इन संस्थाओं की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि वे उनकी आकांक्षाओं को पहले की तरह पूरा करेंगे

सहज ऋण प्रवाह ने बदली ग्रामीण जीवन शैली

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
वित्‍तदायी संस्‍थाओं तक आम आदमी की सहज पहुंच और संस्‍थागत व गैर संस्‍थागत वित्‍तदायी संस्‍थाओं द्वारा आसानी से ऋण सुविधा उपलब्‍ध कराने का परिणाम है कि आज देश के सुदूर गांवों में भी रहन-सहन में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरों में उपलब्‍ध सुविधाएं अब गांवों में सहजता से उपलब्‍ध हो रही हैं। ऐसे में ग्रामीणों की रहन-सहन और उनकी सोच में बदलाव आया है। आज कोई भी व्यक्ति साधन-सुविधाओं की ओर देखाता है और उन सुविधाओं को पाने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो व्यक्ति दो बार सोचता नहीं। यही समय और सोच का बदलाव है।

सारिख्‍यकी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट इस बात की गहराई से पुष्टि करती है। भारत सरकार के सारिख्‍यकी मंत्रालय की व्‍यापक वार्षिक माइयूलर रिपोर्ट के अनुसार शहरों की तुलना में अब गांवों में ऋण लेने वाले अधिक होते जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार गांवों में प्रति एक लाख पर 18714 लोगों में किसी ना किसी तरह का कर्ज लिया है, वहीं शहरी क्षेत्र का यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में

आज फ़ीज, एयर कण्‍डीशनर, महंगे एन्‍ड्रायड

पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करना बंद अंधेरी सुरंग में घुसने जैसा

संजीव	
	
पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों की 24 दिसंबर की रात अफगानिस्तान के पूर्वी पाकटीका प्रांत में एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों की कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के 4 आतंकी ठिकानों पर बम बरसाने का दावा किया है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी कमांडर शेर जमान, कमांडर अबू हमजा, कमांडर अख्तर मुहम्मद और टीटीपी का मीडिया संगठन उमर मीडिया इन ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था। इस एयर स्ट्राइक से भड़की अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इस हमले में महिलाओं और बच्चे समेत 15 निर्दोष नागरिकों की जान जाने का दावा किया है।	

क्या कांग्रेस का ‘वामपंथीकरण’ ही राहुल की नई राजनीति होगी

कमलेश पांडेय	
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यदि उनकी सरकार आई तो सिर्फ जाति जनगणना ही नहीं बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा। दरअसल, इसके जरिए वह पता लगाएंगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है। फिर नई राजनीति शुरू होगी। इससे साफ है कि जेएनयू के युवा वामपंथी नेताओं व कार्यकर्ताओं से भरी कांग्रेस अब उस वामपंथ की राह पर अग्रसर है, जो पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुका है।बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति सर्वेक्षण और आर्थिक समीक्षा की वकालत करते हुए कहा कि इसका मकसद है यह पता लगाना कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में आए तो यह भारत का पहला काम होगा। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फ़न्याय मंच-अब इंडिया बोलेगाफ़्क में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सत्ता में आने के बाद उनका पहला कदम आर्थिक सर्वेक्षण के साथ-साथ जाति जनगणना करवाना होगा।	
उन्होंने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी वाले लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है और वे इस बात से भी अनजान हैं कि उनके पास भारत की कुल सम्पत्ति में से कितनी संपत्ति है। वे कहते हैं कि उनकी आबादी लगभग 50 प्रतिशत है लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके पास कितनी संपत्ति है। इसलिए हम एक जाति जनगणना करेंगे जिससे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को पता चल जाएगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कितनी भागीदारी है। इससे सच्चाई सामने आ जाएगी।फ़्क उन्होंने संकेत दिया कि इससे दलितों,	

अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, गरीब वर्णों को भी उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा।

वही, एक युवा के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, फ़्कआज क्या हो रहा है कि ओबीसी को मूर्ख बनाया जा रहा है और उन्हें बहुत कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है। जाति जनगणना के साथ साथ होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण से पूरे देश को यह पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, गरीब सामान्य वर्ग और महिलाओं के हाथ में कितना धन है।

सबके सामने पूरा साफ हो जाएगा। इसके बाद न्यू पोलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये लोग कहेंगे कि मेरे पचास परसेंट लोग हैं, जबकि मेरे पास 2 परसेंट धन है। इसलिए मुझे 50 परसेंट धन चाहिए। सीधी-सी बात होगी। ये हमारी सोच है, जाति जनगणना पहला कदम है। ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगी बल्कि ये आर्थिक सर्वे भी होगा। हालांकि, राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने बेवद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहाँ ले जा रहे हैं? वहीं, राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अब साफ है कि मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जागीरदारी पुनः पाने के लिए जिस तरह से ओबीसी, दलित, आदिवासी, गरीब वर्णों और महिलाओं को उनके हिस्से की संपत्ति मौजूदा अमीरों से लेकर देना चाहते हैं, उससे विदेशी निवेश प्रभावित

मोबाइल या लवजरी वाहन आसानी से गांवों में देखने को मिल जाते हैं। देखा जाए तो आज पहले वाले गांव नहीं रहे। यह विकास की तस्वीर है। यहां तक कि गांवों में निजी स्कूलों की पहुंच भी हो गई है। आज ग्रामीण भी शहरी नागरिकों की तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छे खानपान पर ध्यान देने लगे हैं।

सहज ऋण उपलब्धता के साइड इफेक्ट भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि कुछ इस तरह के ऋण होते हैं जिन्हें होड़ में ले लिया जाता है और उसका सीधा असर कर्ज के मकड़जाल में फंसने की तरह हो जाता है। सारिख्‍यकी मंत्रालय के आंकड़े यह भी बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऋण लेने में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और ऋण लेने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र अधिकतर ऋण घरेलू जरूरतों को पूरा करने, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, खानपान और शानोशीकत से रहने के लिए पहनावे आदि के लिए लिया जाता है। गंव और शहरों में एक अंतर यह है कि शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी

स्तर पर आसानी से उपलब्ध है, वहीं गांवों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को ऋण लेना पड़ता है। यह सब कृषि कार्यों के लिए लिए जाने वाले ऋण से अलग हट कर है। वैसे भी अधिकांश रथानों पर संस्थागत कृषि ऋण लगभग जीरो ब्याजदर पर या नाममात्र के ब्याज पर उपलब्ध होता है पर नकारात्मक पक्ष यह है कि बिना ब्याज के ऋण को समय पर नहीं चुका कर कर्ज माफ़ी के राजनीतिक जुमले के चलते जीरो ब्याज सुविधा से भी वंचित हो जाते हैं। खैर यह विषय से भटकाव होगा।

शहरों की तरह गांव भी आधुनिकतम सुख-सुविधाओं से संपन्न हो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। विकास की गंगा भी सभी तरफ समान रूप से बहनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता बल्कि यह सबका सपना है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ते कर्ज के पीछे जो चिंतनीय बात है वह यह है कि कहीं ग्रामीण कर्ज के मकड़जाल में फंस कर कुछ पाने की जगह खो अधिक देंगे, इसकी आशंका

हुआ इसके उलट। अफगानिस्तान ने टीटीपी और पाकिस्तान के मसले से साफ हाथ झाड़ लिया। हालांकि, पाकिस्तान का आरोप रहा है कि अफगानिस्तान सरकार की पनाह और समर्थन से टीटीपी पाकिस्तान के भीतर लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी की एक्टिविटी बढ़ गई है। बीते दो साल में खैबर पख्तूनख्वाह और बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएं ज्यादा बढ़ी हैं। इसकी वजह ये है कि ये अफगानिस्तान बॉर्डर के ज्यादा पास हैं। हालत यह है कि इस साल नवंबर तक टीटीपी पाकिस्तान के दो बड़े प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 785 हमलों को अंजाम दे चुका है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 951 फौजियों की मौत हो गई, जबकि 966 लोग जख्मी

अधिक है। इसका बड़ा कारण यह है कि संस्थागत ऋण यानी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण हों या फिर गैर संस्थागत ऋण, परेशानी इनकी वसूली व्यवस्था को लेकर होती है। जितने ऋण देते समय सहदय होते हैं, ऋण की किश्त की वसूली के समय उतने ही बेदर्द होने में कोई कमी नहीं रहती। शहरों में आए दिन रिकवरी एजेंटों के व्यवहार से दो-चार होते देखने में आ जाते हैं। गांवों में तो वसूली करने वालों के टावरों के हालात बदतर ही होंगे। ऐसे में समय रहते इस विषय में सोचना होगा। सरकार और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों के सामने बड़ी जिम्मेदारी अवैयरनेस प्रोग्राम चलाने की है।

दरअसल, जब ऋण प्रदाता संस्था से ऋण लिया जाता है तो उस समय जो डाययूमेंट होता है वह इतना बड़ा और जटिल होता है कि उसे पूरा देखा ही नहीं जाता है और ऋण दिलाने वाला व्यक्ति निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर करने पर जोर देता है। पढ़ा-लिखा और समझदार व्यक्ति भी पूरे डाययूमेंट से गो रूख नहीं होता और परिणाम यह होता है कि बाद में दस्तावेज के प्रावधानों के कारण दो-चार होना पड़ता है।

जिससे गुजरकर दुनिया की दो सुपर पावर रूस और अमेरिका की फौजें शिकस्त खा चुकी हैं। पाकिस्तान की फौजी ताकत और संसाधन, रूस व अमेरिका के मुकाबले क्या हैं, यह सभी को पता है।

अफगान तालिबान से अलग टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। इसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना है। अगस्त, 2008 में पाकिस्तानी सरकार ने टीटीपी को बैन कर दिया था, लेकिन इसकी गतिविधियों को रोक पाने में विफल रहा। हमलों की फेहरिस्त देखें तो साल 2008 में इस्लामाबाद के मरियट होटल और साल 2009 में सेना मुख्यालय पर टीटीपी की तरफ से हमला किया गया था। 2012 में मलाला युसुफ़ज़ई को निशाना बनाने पर पूरी दुनिया का ध्यान इस संगठन की ओर गया। इसी

हस्ताक्षर करने से हाथ बंध जाते हैं। सवाल यह कि अभियान चलाकर यह बताया जाना जरूरी है कि ऋण की एक भी किश्त चुक गए तो कितना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा और यदि दुर्भाग्यवश दो-तीन किश्त नहीं चुका पाये तो हालात बदतर हो जाएंगे और जिस तरह से किसी जमाने में साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे वो ही हालात होने में देर नहीं लगती।

दूसरा यह कि ऋण लेते समय प्राथमिकता भी साफ होनी चाहिए। केवल देखा-देखी ऋण लेने की होड़ भी नुकसानदायक है। गांवों में खेती की जमीन बेच कर अनावश्यक व दिखावे में राशि खर्च करने के दुष्परिणाम सामने हैं। ऐसे में बैंकों और एनजीओ को सामाजिक दायित्व समझते हुए अवैयरनेस प्रोग्राम चला कर लोगों को जागृत करना होगा, नहीं तो कर्ज का यह मर्ज गंभीर रूप लेने में देरी नहीं लगायेगा। जीवन स्तर सुधारने वाली यह सहज वित्त सुविधा साहूकार के कर्ज जाल में फंसने की तरह होकर बहुत कुछ खोने का कारण बन सकती है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आतंकी संगठन ने टीटी 2014 में सबसे बर्बर और वीभत्स हमले को अंजाम दिया, जिसमें पेशावर के सैनिक स्कूल में 150 लोगों मार दिया, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे।

नवंबर, 2021 में पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच सीजफायर समझौता भी हुआ, जिसमें टीटीपी ने उसके समर्थकों को जेल से रिहा करने की मांग की थी। साथ ही कबायली इलाकों से पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को हटाने की मांग की गई, लेकिन यह समझौता महीने भर बाद ही टूट गया। इसके बाद एक साल तक सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत होती रही और कोई समझौता न होने पर टीटीपी ने फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तान में जहां भी संभव हो, उसके लड़ाके हमला करें।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

‘वामपंथीकरण’ ही राहुल की नई राजनीति होगी

होगा। धनी लोग अपनी संपत्ति विदेशों में शिफ्ट करने लगेंगे। इससे हर ओर असंतोष फैलेगा और देश में अरब देशों की तरह गुह युद्ध होगा, क्योंकि इतनी आसानी से लोग अपनी सम्पत्ति छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि देश में अब ग्राम भूमि सवर्णों से ओबीसी-दलितों-अल्पसंख्यकों-आदिवासियों की ओर हस्तांतरित होती जा रही है। यह कांग्रेस की सरकारों की नीतियों और उनको हटाकर विकसित हुई समाजवादी राजनीति करने वाले दलों की नीतियों की कसमאת है। वही, शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे सवर्णों के पास शहरी सम्पत्ति बढ़ी है, लेकिन ओबीसी-दलितों-आदिवासियों-अल्पसंख्यकों आदि ने भी ऐसी नई सम्पत्ति खूब बनाई है। इससे संपत्ति के समान बंटवारे का उनका विचार पिछले लोकसभा चुनाव 2024 की तरह ही उन पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि तब वह केंद्रीय सत्ता में आते आते यदि चूक गए तो उसके पीछे उनकी इन्हीं बयानबाजियों का हाथ है।

देखा जाए तो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में सरकारी नौकरियों में जातीय आरक्षण जैसे निक्छे विचार के बाद जनसंख्या आधारित संपत्ति के बंटवारे का विचार कांग्रेस का ऐसा जाहिल विचार है जो भारत के विकास को पुनः अवरुद्ध कर देगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस रणनीतिकार चीनी-रूसी साठगांठ से प्रभावित और सीआईए-आईएसआई के बैक डोर पॉलिसी आधारित षडयंत्रों से अनुप्राणित हैं, जिनका मकसद है कि अमेरिका, रूस, चीन के समकक्ष स्तर तक उठ चुके मोदी युगीन भारत को उलजुलूल सियासी विवादों में फंसाकर पीछे धकेल दिया जाए। यदि इसे समझने में राहुल गांधी नादानी दिखा रहे हैं तो यह एक

खतरनाक राजनीतिक ट्रेंड है, जिस ओर भाजपा भी इशारा कर चुकी है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की मांग पर अड़े रहने से राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव 2029 में बहुमत भी मिल सकता है, क्योंकि मुत्तसरों राजनीति एक बार सेना के लोकसभा चुनाव के रेटरीरेंट, होटल आदि भी बहुत बड़ी संपत्ति बन चुकी हैं। चर्चा है कि ये सम्पत्ति पहले कांग्रेसी नेताओं व उसके समर्थकों के पास ज्यादा थी, जिसे बचाने के लिए लोग भाजपाईय समाजवादी बन चुके हैं। कुछ लोग तो दलितवादी या आदिवासी दलों से भी जुड़ चुके हैं। इसलिए राहुल को बताना चाहिए कि वो किस-किस चीज की गणना करेंगे। सबसे बड़ी बात शिक्षा और हुनर जो मानव संसाधन है, उससे ही उपर्युक्त सम्पत्ति खड़ी होती है, उसका बंटवारा कैसे करेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, जो अवसर अपने बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उनका एक बयान ही अब उन पर भारी पड़ रहा है।

व्योक्ति यूपी के बरेली जिले की एक अदालत ने उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। जिसके मुतालिक राहुल गांधी को सात जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने बताया कि बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने बयान को लेकर गत शनिवार को गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तारीख तय की है।

बता दें कि बरेली के सुभाषनगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाटक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और

और निजी संपत्ति। नामी सम्पत्ति और बेनामी सम्पत्ति। भूमि संपत्ति और मौद्रिक संपत्ति। मकान, दुकान, कोठी, फेक्ट्री, स्वर्णभूषण आदि। विभिन्न प्रकार के वाहन, मशीन, गैजेट्स आदि। आजकल राजनीतिक दल, कम्पनी, एनजीओ, ट्रस्ट, फर्म, स्कूल, कॉलेज, विश्विद्यालय, रेस्टोरेंट, होटल आदि भी बहुत बड़ी संपत्ति बन चुकी हैं। चर्चा है कि ये सम्पत्ति पहले कांग्रेसी नेताओं व उसके समर्थकों के पास ज्यादा थी, जिसे बचाने के लिए लोग भाजपाईय समाजवादी बन चुके हैं। कुछ लोग तो दलितवादी या आदिवासी दलों से भी जुड़ चुके हैं। इसलिए राहुल को बताना चाहिए कि वो किस-किस चीज की गणना करेंगे। सबसे बड़ी बात शिक्षा और हुनर जो मानव संसाधन है, उससे ही उपर्युक्त सम्पत्ति खड़ी होती है, उसका बंटवारा कैसे करेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी, जो अवसर अपने बयान के चलते सुर्खियों में रहते हैं, उनका एक बयान ही अब उन पर भारी पड़ रहा है।

व्योक्ति यूपी के बरेली जिले की एक अदालत ने उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। जिसके मुतालिक राहुल गांधी को सात जनवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अधिवक्ता वीरेन्द्र पाल गुप्ता ने बताया कि बरेली जिला एवं सत्र न्यायालय ने बयान को लेकर गत शनिवार को गांधी को नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तारीख तय की है।

बता दें कि बरेली के सुभाषनगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाटक ने अधिवक्ताओं गुप्ता और

अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सांसद-विधायक अदालत एम्पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। व्योक्ति राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे। इस सर्वे के आधार पर संपत्ति का बंटवारा होगा। जिसकी भागीदारी अधिक होगी अगर उसकी संपत्ति कम है। वो कम आबादी जिसकी संपत्ति ज्यादा है, उससे लेकर कम संपत्ति वालों को दी जाएगी। इसलिए राहुल के इस बयान का काफी विरोध हो रहा था।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिसकी तब खूब आलोचना हुई थी। वैसे आपातकाल के दौरान भी वामपंथियों ने कांग्रेस का साथ दिया था। हल पटक दो खेत हमारा- वाले नारे और सिक्किम कानून को भी कांग्रेस का समर्थन हासिल था, जो रूस से उसकी दोस्ती का प्रतिकूल था। उसके और उसके समाजवादी मित्रों के कार्यकाल में नवसत्तवाद, अलगाववाद और आतंकवाद भी खूब फला-फूला। इसलिए कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अन्यथा वह वामपंथियों की तरह कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में खुद ही अपना बड़ा योगदान देगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

देहात संदेश

पीकेएल सीजन 11 के प्लेऑफ की शुरुआत, शीर्ष 6 कोवों ने की युवा सितारों की प्रशंसा

एजेंसी पुणे। पीकेएल सीजन 11 का प्लेऑफ सप्ताह 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पीकेएल का बैटल रॉयल शीव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे से शुरू होगा। पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धाओं के बीच होगा। दोनों टीमों ने कभी खिताब नहीं जीता है। वहीं, तीन बार की चैंपियन पटना पाइरेट्स, सीजन 8 की विजेता दबंग दिल्ली के.सी., सीजन 1 और 9 की खिताब धारक जयपुर पंकि पैथर्स और सीजन 2 की चैंपियन य मुंबा की टीमें भी लीग चरण के आखिरी गेम के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालीफिकेशन सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार की कड़ी टक्कर से स्पष्ट है कि यह सीजन कितना प्रतिस्पर्धी रहा है। कबड्डी के खेल के छह कोच मनप्रीत सिंह (हरियाणा स्टीलर्स), जोगिंदर नरवाल (दबंग दिल्ली के.सी.), जसवीर सिंह (यूपी योद्धा), नरेंद्र रेधु (पटना पाइरेट्स), घोलमरेजा माजंखानी (यु मुंबा) और संजीव बालियान (जयपुर पंकि पैथर्स) ने पंगा राउंडटेबल में विस्तार से बात की और पीकेएल सीजन 11 के विभिन्न पहलुओं पर बात की।

महेश्वरी और अनंतजीत ने राजस्थान के लिए स्कीट मिश्रित टीम का राष्ट्रीय खिताब जीता

नई दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नास्का की जोड़ी ने अपने राज्य राजस्थान के लिए स्कीट मिश्रित टीम का राष्ट्रीय खिताब जीतकर साल का अच्छा समापन किया। 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के दौरान डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (खेकएसएसआर) में खेले गए फाइनल में इस जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के मेराज अहमद खान और अरेबा खान को 44-43 के करीबी स्कोर से हराया। पंजाब की गमेत सेकॉन और अभय सिंह सेकॉन की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले दिन में, महेश्वरी और अनंतजीत ने तीन 25-शॉट राउंड में क्रमशः 72 और 71 का स्कोर करके सात टीमों के क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया। तीन टीमें- गमेत और अभय, हरियाणा के इशान लिब्रा और रायजा डिल्लों, और मेराज और अरेबा ने 141 के समान स्कोर किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जोड़ी ने आठ लगातार लश्च साधकर तीन-तफ्फा शूट-ऑफ में जीत हासिल की और स्वर्ण के लिए मुकाबला करने का अधिकार प्राप्त किया। महेश्वरी और अनंतजीत ने आत्मविश्वास से भरे हुए फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और छह श्रृंखलाओं के दौरान लगातार नेतृत्व बनाए रखा, लेकिन महेश्वरी को उनके शॉट समय की सीमा पार करने के कारण चेतावनी मिलने और ध्यान की कमी ने अंत में इसे और भी करीब बना दिया।

खेलों के माध्यम से खिलाड़ी अपने शहर, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं : प्रिया अग्रवाल

मुरादाबाद। मंडलीय ओलम्पिक संघ एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय के तत्वावधान में मंडल स्तरीय बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से खिलाड़ी अपने शहर, राज्य और राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। हम सभी को खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करना चाहिए। इस टूर्नामेंट में मंडल के विभिन्न जिलों के लगभग 250 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उप ओलम्पिक संघ के क्षेत्रीय सचिव डॉ. अजय पाठक ने मंडल स्तरीय बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि अंडर-15 बालक डबल्स में विजेता रहे अश्विन कुमार (शिरडी साईं), शिवम शर्मा (सोनकरपुर स्ट्रेडियम) की जोड़ी ने यश चौहान जीके बेलहम एवं विशिष्ट चतुर्वेदी (सिंगमफील्ड) की जोड़ी 21-15, 12-21, 21-18 से हराकर चौम्पियन बना। अंडर-15 बालक सिंगल्स विशिष्ट चतुर्वेदी (सिंगमफील्ड) ने यश चौहान (जीके बेलहम) को 21-12, 12-21, 21-17 से हराकर चौम्पियन बना। अंडर-19 बालक डबल्स पीपूष आहुजा एवं शीर्ष मिश्रा (स्ट्रेडियम) की जोड़ी ने अनन्त कपूर (गोल्डन गेट) एवं मयंक यादव (स्ट्रेडियम) की जोड़ी को 15-21, 21-19, 24-22 से हराकर चौम्पियन बना। अंडर-19 बालक सिंगल्स मयंक यादव (स्ट्रेडियम) ने पीपूष आहुजा (स्ट्रेडियम) को 21-15, 15-21, 21-19 से हराया। अंडर 15 बालिका डबल्स अवनी सिंह (एस0एससीए) एवं श्रेया सिंह ने अर्विंद सिंह (केन्द्रीय विद्यालय) एवं मानसी (मैथोडिस्ट) 21-12, 10-21, 21-19 से हराया। अंडर-19 बालिका डबल्स अवनी सिंह (एसएससीए) एवं अक्षिता (पीएमएस) ने अराधना शर्मा एवं प्रियाशी यादव 21-15, 21-18 से हराया।

राज्य स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का स्वागत

मुरादाबाद। मेरठ के मिलेनियम पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई एक दिवसीय राज्यस्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण व रजत पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का आरएसडी स्पोर्ट्स एकेडमी में स्वागत अभिन्नंदन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 15 से अधिक जिलों के 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। रोलर स्केटिंग के कोच शाहवेज अली ने बताया कि आरएसडी स्पोर्ट्स एकेडमी मुरादाबाद के चार खिलाड़ियों ने 22 दिसंबर को मेरठ में हुई एक दिवसीय राज्यस्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था।

वेस्ट ब्रोम छोड़ने के बाद कार्लोस कोरबेरन ने संभाली वालेंसिया की कमान

एजेंसी मैड्रिड। ला लीगा के संयुक्त निचले क्लब वालेंसिया ने कार्लोस कोरबेरन को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। इंग्लिश चैंपियनशिप टीम वेस्ट ब्रोमविच एल्ब्यन को छोड़कर आए 41 वर्षीय कोरबेरन स्बेन बाराजा की जगह लेंगे। पूर्व कोच स्बेन बाराजा को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया था।

इससे पहले वालेंसिया ने अपने घरेलू मैदान पर अलावेस के साथ 2-2 से ड्रा खेला था। इस मैच से पहले टीम ने अपने पहले 17 मैचों में केवल 12 अंक ही अर्जित किए थे। माना जा रहा है कि वालेंसिया ने कोरबेरन के रिलीज क्लॉज के लिए करीब तीन मिलियन यूरो का भुगतान किया है। वेस्ट ब्रोम ने एक बयान में पुष्टि की, एल्ब्यन ने कार्लोस कोरबेरन के क्लब छोड़ने और ला लीगा की टीम

वालेंसिया के साथ एक नया अवसर तलाशने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत जताई है। 41 वर्षीय खिलाड़ी



हमारे आधार के साथ अपने वतन लौटने के लिए तैयार है। वहीं, कोरबेरन ने कहा कि यह निर्णय मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। उन्होंने कहा, इस विशेष क्लब के लिए मेरे दिल में हमेशा एक जगह रहेगी और मुझे उम्मीद है कि

एक दिन मैं आप सभी के अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए वापस आ पाऊंगा। वेस्ट ब्रोम में अपने कार्यकाल के दौरान, कोरबेरन ने अपने पहले सीजन में क्लब को नौवें और पिछले सीजन में इसे पांचवें स्थान पर पहुंचाया, जबकि वर्तमान में यह चैंपियनशिप तालिका में सातवें स्थान पर है।

कार्यकाल के दौरान, कोरबेरन ने अपने पहले सीजन में क्लब को नौवें और पिछले सीजन में इसे पांचवें स्थान पर पहुंचाया, जबकि वर्तमान में यह चैंपियनशिप तालिका में सातवें स्थान पर है।

संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध पर ऐतिहासिक संधि को अपनाया

एजेंसी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आज साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए एक नई संधि को अपनाया, जिसके साथ ही पांच साल की वार्ता प्रक्रिया पूरी हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटीनियो गुटेरेस ने सभी देशों से संधि में शामिल होने और संबंधित हितधारकों के सहयोग से इसे लागू करने का आह्वान किया है। साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधि का उद्देश्य साइबर अपराध को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से रोकना और उससे निपटना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना शामिल है, खासकर विकासशील देशों के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कहा “हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में समाज के विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साइबर अपराध के संभावित खतरे को भी बढ़ाती हैं। इस सम्मेलन को अपनाने के साथ, सदस्य देशों के पास साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने, लोगों और उनके अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उपकरण और साधन उपलब्ध हैं। इसम और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) ने वार्ता के सचिवालय के रूप में कार्य किया।

शक्कर में मांग, खाद्य तेलों में तेजी, दलहन नरम, दाल- चावल सामान्य

इंदौर। सियागंज किराना बाजार में शक्कर में उठाव रहा। खाद्य तेलों में लिवाली से भाव तेजी लिए रहे। तिलहनों में रिफाइनरी प्लांटों की खरीदी रही। दलहनों में मांग सुस्ती के साथ आवक दबाव से तुअर में नरमी दर्ज की गई। आज दाल तथा चावल में कामकाज सामान्य वत बना रहा।

किराना बाजार

सियागंज किराना बाजार में शक्कर में उठाव बताया गया। आज शक्कर में चार गाड़ी की आवक हुई। खोपरा गोला दिसावर के साथ ऊंचा होकर बिका। खोपरा बुरा तथा हल्दी में मांग सुधार लिए बताई गई।

तेल-तिलहन

खाद्य तेलों में लिवाली सुधार से सोयाबीन रिफाईंड तेजी लिए रहा। तिलहन में उठाव से सरसों में मजबूती दर्ज की गई। सोयाबीन में लिवाली बताई गई।

दाल-दलहन

संयोगितागंज अनाज मंडी में दलहन जिसनों में कामकाज सुस्ती लिए बताया गया। तुअर घटकर बिकी। दाल में उठाव रहा। चावल में लिवाली से भाव स्थिरता लिए बताए गए।

गोमैकेनिक 700 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य पाने के बाद लाएगी आईपीओ: सीईओ

नयी दिल्ली। यात्री वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत सेवाएं देने वाली कंपनी गोमैकेनिक को उम्मीद है कि वर्ष 2027 तक उसका शुद्ध राजस्व तीन गुना होकर 700 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। इसके बाद वह शेयर बाजार में सूचीबद्धता का रुख करेगी। गोमैकेनिक के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिमांशु अरोड़ा ने बातचीत में कहा कि कंपनी की वाहन सर्विसिंग बाजार में फिलहाल करीब तीन प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसे अगले तीन वर्षों में बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। गोमैकेनिक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 210 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसने 85 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। अरोड़ा ने कहा, “अभी हमारी बाजार हिस्सेदारी करीब तीन प्रतिशत पर है और 2027 तक यह करीब 10 प्रतिशत हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि 2027 तक हमारा ब्रांड लगभग 700 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करेगा। हमारा मानना ​​है कि गोमैकेनिक की कहानी का अगला स्वाभाविक कदम आर्थिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) होगा।”

सीमेंट उद्योग में इस साल बड़ी कंपनियों में दिखी विलय और अधिग्रहण की होड़

नयी दिल्ली। भारतीय सीमेंट उद्योग 2024 में दो बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बीच छोटी कंपनियों के अधिग्रहण को लेकर बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और एकीकरण का गवाह रहा है। अगले साल सीमेंट उद्योग बिक्री से प्राप्ति में सुधार, ऊंचे मार्जिन और मांग में तेजी के साथ-साथ बड़ी ढांचगत परियोजनाओं पर सरकार के बढ़ते खर्च से बिक्री में लगभग आठ प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। दो प्रमुख कंपनियों – आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट और अरबगौत गौतम अदाणी की अगुवाई वाली अंबुजा सीमेंट्स द्वारा 4.5 अरब डॉलर में पांच करोड़ टन सालाना से 7?अधिक की क्षमता का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा, इन कंपनियों ने मौजूदा इकाइयों का विस्तार भी किया है, क्योंकि उन्होंने अवसरों की तलाश में अपनी पूंजी तैयार रखी है। उद्योग को 2024 में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें मध्यम क्षमता उपयोग से लेकर कम बिक्री प्राप्ति तक शामिल है। इससे कई सीमेंट विनिर्माताओं की आमदनी प्रभावित हुई।

ईपीएफओ ने अक्टूबर महीने में 13.41 लाख सदस्य जोड़े

एजेंसी नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अक्टूबर महीने में शुद्ध रूप से 13.41 लाख सदस्य जोड़े हैं। इस दौरान ईपीएफओ ने अपने साथ 7.50 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। यह रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि ईपीएफओ ने अक्टूबर 2024 में नेट 13.41 लाख सदस्य?यों को जोड़ा है। इस दौरान ईपीएफओ से 7.50 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। ईपीएफओ के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में 18-25 आयु वर्ग के जोड़े गए कुल नए सदस्य?यों की संख्या 5.43 लाख है। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के दौरान 18-25 आयु वर्ग का दबदबा रहा है, जो अक्टूबर

2024 में जोड़े गए कुल नए सदस्यों का 58.49 फीसदी है। ईपीएफओ के अक्टूबर 2024



के लिए जारी आंकड़ों से चलता है कि लगभग 12.90 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और बाद में फिर से जुड़ गए। इस दौरान

6जी की वैश्विक दौड़ में आगे निकलने को तैयार भारत : सीओएआई

एजेंसी नई दिल्ली।

सेलुलर ऑपरेटयों के संघ सीओएआई ने आज कहा कि टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को गति देने के लिए उत्साहजन अवसर और सरकार के जबरदस्त प्रयास की बदौलत भारत अब इंटरनेट की छठी पीढ़ी 6जी की वैश्विक दौड़ में आगे निकलने के लिए तैयार है। सीओएआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. एस. पी. कोचर ने मंगलवार को भारत के दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि के लिए वर्ष 2024 की उपलब्धियों और रूपरेखा को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय दूरसंचार उद्योग ने हाल के वर्षों में एक शानदार यात्रा करते हुए इस देश की सामाजिक आर्थिक वृद्धि

के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया है। देश में 1.2 अरब से अधिक दूरसंचार ग्राहक के कारण



अक्टूबर,2024 तक प्रति वायरलेस डेटा उपभोक्ता का औसत मासिक डेटा उपयोग 21.30 जीबी (गीबीबाइट) तक पहुंच गया है। डॉ. कोचर ने कहा कि अक्टूबर, 2024 तक 4,60,592 बीटीएस साइट्स स्थापित किए जा चुके हैं जिससे

5जी यूजर का आधार बढ़कर 12.5 करोड़ पहुंच गया और वर्ष 2026 तक इसके 35 करोड़ तक पहुंचने

का अनुमान है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यू) भारत में एक प्रमुख 5जी यूज केस के तौर पर उभरा है और लॉजिक के एक साल के भीतर इसके कनेक्शंस की संख्या करीब 30 लाख पहुंच गई है। जीडीपी में एक बड़ा योगदान करने वाला यह

ओला इलेक्ट्रिक ने खोले 3200 नये शोरूम

एजेंसी

बंगलुरु। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने आज पूरे देश में 3200 से अधिक नये शोरूम शुरू करने की घोषणा की जिससे उसके शोरूम की संख्या बढ़कर चार हजार हो गयी है। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि 3200 से अधिक नए स्टोर खोले गये हैं जो सर्विस सेंटरों के साथ जुड़े हैं, इससे भारत में सबसे बड़े ईवी नेटवर्क का विस्तार हुआ है। यह विस्तार सिर्फ मेट्रो और टियर 1 तथा 2 शहरों तक ही नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और तहसीलों तक हुआ है, जिससे पूरे देश में ईवी की पहुंच और भी आसान हो गई है।

उसने आज अपने नेटवर्क को 4,000 स्टोर्स तक बढ़ाने की घोषणा की जो मौजूदा नेटवर्क से चार गुना ज्यादा है। यह दुनिया में ईवी नेटवर्क के सबसे बड़े विस्तारों में से एक माना जा रहा है, इस विस्तार से यकीनन देश में ईवी तक लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी और ईवी के क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होने की संभावनाएं भी

काफी हद तक बढ़ जाएंगी साथ ही ईवी के प्रति भरोसा और उसे अपनाने को मजबूती भी मिलेगी। इस विस्तार के साथ ओला



इलेक्ट्रिक ने अपने सेविंग वाला स्कूटर अभियान के तहत किए गए वादे को पूरा कर दिया है।कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भाविष अग्रवाल ने कहा हमने जो वादा किया था, उसे आज पूरा कर दिखाया है। भारत के ईवी के सफर में आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क का विस्तार हर शहर, हर कस्बे और हर तालुका तक कर दिया है। हमारे नए स्टोर्स, जो सर्विस सेंटरों के साथ जुड़े हैं, उन्होंने ईवी खरीदने और उसे इस्तेमाल करने के

अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया है। सेविंग वाला स्कूटर अभियान के साथ हमने नए मानक स्थापित किए हैं। जैसे-जैसे हम उन्नत हो रहे हैं, हम



इन्वेंवेशन की सीमाओं को नया आयाम देने और देश को इंडआईसीईशेज की ओर तेजी से ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही कंपनी ने मूवओएस 5 बीटा के लिए प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं, जिसमें ग्रुप नैविगेशन, लाइव लोकेशन शेयरिंग, रोड ट्रिप मोड (ओला मैप्स द्वारा संचालित) जैसे फीचर्स शामिल हैं। कंपनी ने एप्स 1 पोर्टफोलियो पर लगभग 25,000 रुपये तक के ऑफरों की भी घोषणा की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था चालू और अगले वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी: ईवाई रिपोर्ट

एजेंसी नई दिल्ली।

भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2024-25 और अगले वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है। इसकी वजह निजी उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में गिरावट है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान से कहीं कम 5.4 फीसदी रही है, जो सात तिमाहियों का सबसे निचला स्तर है।

इससे पिछली तिमाही अप्रैल-जून तिमाही में वृद्धि दर 6.7 फीसदी थी। ईवाई इकोनॉमी वॉच की जारी नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2047-48 तक विकासवृद्धि भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के राजकोषीय दायित्व

ढांचे में सुधार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में उन



प्रमुख राजकोषीय और आर्थिक उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, जो इस वृद्धि प्रक्षेपक को बनाए रख सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। ईवाई वॉच रिपोर्ट में कहा गया है

कि टिकाऊ ऋण प्रबंधन, सरकारी बचत को खत्म करने तथा निवेश



आधारित वृद्धि को बढ़ावा देने से भारत के विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का मार्ग प्रशस्त होगा। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी. के. श्रीवास्तव ने राजकोषीय

उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत को राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए सतत विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए जरूरी बताया है। अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड का टेड नाम EY ईवाई है। ये इंग्लैंड में स्थित एक ब्रिटिशबहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा साझेदारी कंपनी है। ईवाई दुनिया के सबसे बड़े पेशेवर सेवा नेटवर्क में से एक है। डेलोइट, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी के साथ इसे बिग फोर अकाउंटिंग फर्मों में से एक माना जाता है। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीओ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर अब 6.6 फीसदी कर दिया है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए अगले 25 साल का खाका तैयार किया है: फडणवीस

नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए अगले 25 साल का खाका तैयार किया है। उन्होंने



यहां ‘प्रेस से मुलाकात’ कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गरीब लोगों को दिए जाने वाले मकानों में सौर ऊर्जा सुविधा उपलब्ध करने की योजना बना रही है। फडणवीस के पास ऊर्जा विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन साल में बिजली की दरें कम करने की भी कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “ ऊर्जा क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है और हमने इसके लिए अगले 25 साल का खाका तैयार किया है।” उन्होंने कहा, “ हमारी योजना यह भी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत गरीबों को दिए जाने वाले मकानों का बिजली का बिल न आए। इन मकानों को सौर ऊर्जा के तहत लाया जाएगा।”

2024 में सोने ने कराया जोरदार मुनाफा, 27 प्रतिशत रिटर्न से निवेशकों की बल्ले-बल्ले

एजेंसी नई दिल्ली। सोने के निवेशकों को साल 2024 में जमकर फायदा हुआ है। इस साल सोने ने करीब 27 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों को काफी फायदा हुआ है। माना जा रहा है कि जियो-पॉलिटिकल टेंशन और वैश्विक अर्थव्यवस्था के उपल-पुलत की वजह से इस साल निवेशकों ने सोने को सफ इन्वेस्टमेंट मानते हुए जमकर पैसे लगाए। इसके साथ चीन

समेत कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को मजबूत करने की इरादे से जमकर खरीदारी की। इसीलिए साल 2024 सोने की जबरदस्त तेजी का गवाह बन गया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की सर्राट् चाल पर मामूली ब्रेक भी लगा। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद होने वाले संभावित नीतिगत परिवर्तनों की आशंका ने

डॉलर इंडेक्स को मजबूत किया है, जिसकी वजह से सोने की मांग में कुछ कमी भी आई है। इसके बावजूद बुलियन को डिमांड में तीसरी तिमाही के दौरान आई तेजी की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर तेजी आने की उम्मीद बन गई है। मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान पहली बार सोने की डिमांड 100 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गई है। जाकारों का कहना है कि इस साल सोने की

कीमत में आई जोरदार तेजी के लिए मुख्य रूप से इजरायल और ईरान के बीच बने जंग जैसे हालात, रूस और यूक्रेन यूक्रेन में जारी जंग और सौरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की विद्रोहियों से हुई हार को जिम्मेवार माना जा सकता है। इन तीनों वजहों से सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में सोने की मांग में तेजी आई। बुलियन मार्केट एक्सपर्ट मयंक मोहन के अनुसार साल 2024 में कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की

खरीदारी करते रहे। साल 2025 में भी केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस तरह अगले साल भी सोने के सबसे बड़े लिवाल अलग-अलग देशों के बैंक ही रहने वाले हैं। और तेजी आ सकती है। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा व्याज दरों में कटौती किए जाने की वजह से निवेशकों के लिए सोना आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसके साथ ही

सम्रपट चाल में भागता रहेगा। इस बीच यदि जियो-पॉलिटिकल टेंशन में बढ़ोतरी हुई, तो इन्वेस्टर भी बड़ी तादाद में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से सोने के भाव में और तेजी आ सकती है। कैपेक्स गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता का कहना है कि अमेरिकन फेडरल रिजर्व द्वारा व्याज दरों में कटौती किए जाने की वजह से निवेशकों के लिए सोना आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसके साथ ही

महंगाई के खतरे को देखते हुए भी कई बड़े निवेशकों ने सोने में पैसा लगाने का फैसला किया है, जिसकी वजह से इस धातु की कीमत में लगातार तेजी आई है। आने वाले दिनों में भी सोने में तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है। खासकर, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और सिटी ने साल 2025 में सोने की कीमत बढ़ कर 3,000 से 3,100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाने की उम्मीद जताई है।

